>

Title: Need to protect the interest of small retailers keeping in view the advent of Multinational Companies in the retail sector.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सचिवों की समिति की 51 प्रतिशत की सिफारिश से खुदरा बाजार में लगे देश के कोने-कोने में किराना व छोटे-मझोले व्यवसाय करने वाले व्यापारियों तथा कामगारों के हित इस कदम से चरमराने वाले हैं और लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुचक्र में फंस कर दशकों पुरानी यह व्यवस्था दम तोड़ देगी।

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी और थोक बाजार में 100 फीसदी की अनुमति एफडीआई को मिली हुई है। परिणामस्वरूप देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हिस्सेदारी बाजार पर 15 फीसदी के आसपास है और यदि सचिवों की समिति की संस्तुति को सरकार मान लेती है तो देश के बाजारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हिस्सेदारी 15 से बढ़कर 100 फीसदी हो जाएगी जिससे देश का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित होगा और पिछड़ जाएगा।

मेरा आग्रह है कि एफडीआई की अनुमति देने से पूर्व हर पहलू पर बड़ी सावधानी से विचार हो और सुनिश्चित हो कि छोटे व्यापारियों को इन अनुमति से नुकसान न हो, नहीं तो आगे चलकर परिणाम घातक होंगे।